प्रेरणा

यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा 'आप' शब्द का, उसके बाद 'हम' शब्द का और सबसे कम 'मैं' शब्द का उपयोग करना चाहिए।

सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	33°	25°
शनिवार	30°	24°
रविवार	33°	26°
सोमवार	32°	26°
मंगलवार	32°	27°
बुधवार	31°	26°
वीरवार	31°	26°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 29 AUGUST TO 04 SEPTEMBER 2025 • VOLUME 06 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!

Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?

Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?

Should I consider Computer or Mechanical Engineering?

What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?

Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?

Do I have the aptitude for Architecture and Designing?

Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

भारतीय सेना ने जम्मू, हिमाचल व पंजाब में चलाया राहत अभियान

बाढ़ में फंसे अब तक कुल 1,211 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगातार बारिश और बढ़ते जल स्तर के बाद, भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की आवश्यकता के आधार पर व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान शुरू किया। ये अभियान सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए तेज़ी से चलाए गए जिसका एकमात्र उद्देश्य नागरिकों को राहत और बचाव प्रदान करना था। सभी कार्य स्थानीय राज्य प्रशासन के समन्वय में किए गए। सेना के विमानन और थल बलों द्वारा त्वरित और दृढ़ कार्रवाई से जम्मू, मामून, पठानकोट (सांबा, कचले, सुजानपुर), गुरदासपुर (मकौरा पट्टन, अदालतगढ़), अमृतसर और फिरोजपुर सेक्टरों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत मिली है। राहत कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा दलों और संचार संसाधनों सहित कुल 28 सैन्य टुकड़ियाँ सक्रिय की गई हैं। ये टुकड़ियाँ विस्थापित परिवारों को तत्काल ज़मीनी स्तर की सहायता, निकासी सहायता, संपर्क बहाल करने और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही हैं। सेना विमानन संसाधनों ने बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बारह हेलीकॉप्टरों - जिनमें तीन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और नौ चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं - ने चुनौतीपूर्ण विंचिंग और होवरिंग ऑपरेशनों को अंजाम दिया, छतों पर और जलमग्न गाँवों में फंसे असंख्य नागरिकों को बचाया, जो सेना के एविएटर्स की उच्च सटीकता और साहस को दर्शाता है। इसके अलावा, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए नावों और सुरक्षा रस्सियों का उपयोग किया जा रहा है।

अब तक कुल 1,211 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है, जिनमें माधोपुर बैराज में फंसे 11 पंजाब सरकार के अधिकारी और 180 पीएमएफ कर्मी भी शामिल हैं। राहत सामग्री वितरण भी प्राथमिकता रही है। सेना के हेलीकॉप्टरों और ज़मीनी टीमों द्वारा कट-ऑफ क्षेत्रों में भोजन, पानी और दवाओं सहित लगभग 2,300 किलोग्राम आवश्यक आपूर्ति गिराई या वितरित की गई है। चिकित्सा दल घायलों और कमज़ोर लोगों को मौके पर ही सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय सेना के एचएडीआर ऑपरेशन राज्य प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर चौबीसों घंटे चलाए जा रहे हैं। चल रहे ऑपरेशन सेना की सेवा और बलिदान की भावना को रेखांकित करते हैं, क्योंकि सैनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और एविएटर जान बचाने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं।

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,600 लोगों को बचाया, 88 राहत कैंप स्थापित

24X7 स्टेट बाढ़ कंट्रोल रूम पूरी स्थिति पर नज़र रखने के इलावा बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रदान कर रहा सहायता

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,600 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर स्थापित राहत शिविरों में पहुंचाया है। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल और पंजाब पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने जालंधर में स्टेट बाढ़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पूरे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए जालंधर में एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम (0181-2240064) स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित लोगों तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि बाढ़ से कुल 835 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें अमृतसर में 14, बठिंडा में 21, बरनाला में 7, लुधियाना में 20, पठानकोट में 81, फाजिल्का में 20, मानसा में 11, तरनतारन में 45, एस.बी.एस. नगर में 3, मलेरकोटला में 1, श्री मुक्तसर साहिब में 64, संगरूर में 22, फिरोजपुर में 93, एस.ए.एस. नगर में 1, कपूरथला में 107, गुरदासपुर में 202, फतेहगढ़ साहिब में 1, मोगा में 35, रूपनगर में 2 और होशियारपुर में 85 गांव शामिल है। उन्होंने बताया कि 6,600 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है, जिनमें फ़िरोज़पुर में 2007, गुरदासपुर में 2200, पठानकोट में 1100, कपूरथला में 220, होशियारपुर में 1052 और मोगा में 20 लोग शामिल है। सभी को सरकार द्वारा स्थापित 88 राहत शिविरों में भेजा गया है।

सीएम, कैबिनेट मंत्री व सभी 'आप' विधायक देंगे एक महीने का वेतन

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूरी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी (आप) के सभी विधायकों के साथ मिलकर प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि प्रकृति के कहर के कारण पंजाब को काफी नुकसान हुआ है और यह ऐसा समय है, जब सभी पंजाबियों को एक-दूसरे का हाथ थामने के लिए आगे आना चाहिए।

राहत और बचाव कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं : भगवंत मान

ब्यास (जालंधर ब्रीज). पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने के साथ-साथ बाढ़ के कारण डूबे हुए गांवों में फंसे परिवारों को सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकस्मिक दौरा किया जिसके दौरान स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें बाढ़ के कारण खड़ी फसलों, मकानों, सार्वजनिक इमारतों और पशुधन को हुए नुकसान की जानकारी दी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों को बाहर निकालने के लिए वचनबद्ध है और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों को राहत के लिए पहले ही फंड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर जिलों को और फंड भी आवंटित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पूरे जोश से काम कर रही है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया, जल जनित और वेक्टर बोर्न बीमारियों की रोकथाम संबंधी विस्तृत समीक्षा के लिए सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), रेड क्रॉस और केमिस्ट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य संसाधन जुटाने का ऐलान किया। विभाग ने 360 मोबाइल मेडिकल टीमें और 458 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित की हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। मंत्री ने बताया कि बाढ़ राहत के लिए कुल 172 एम्बुलेंसें दिन-रात तैनात हैं। उन्होंने सिविल सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सहायता से वंचित न रहे।

हरियाणा ने पंजाब के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

चंडीगढ़. पंजाब उत्तरी राज्यों में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से उत्पन्न भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया है और मंत्रियों को स्थिति नियंत्रण में आने तक प्रभावित क्षेत्रों में ही रहने का निर्देश दिया है। लोगों को निकालने, संपत्ति की सुरक्षा और निर्बाध राहत अभियान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एकजुटता दिखाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान को पत्र लिखकर बाढ़ से निपटने के लिए पूरी मदद की पेशकश की। यह कदम ऐसे समय में अंतर-राज्यीय सहयोग को रेखांकित करता है जब बढ़ता जलस्तर ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती इलाकों में तबाही मचा रहा है। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर नुकसान को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का समय नहीं है।

महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य सरकार 25 सितंबर से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करेगी जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये मासिक सहायता मिलेगी, जो सत्तारूढ़ भाजपा का प्रमुख चुनावी वादा पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की, जिसमें योजना के कार्यान्वयन से संबंधित एकल एजेंडा को मंजूरी दी गई। सैनी ने बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना 25 सितंबर, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लागू होगी।

एससी समुदाय की शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी और हेल्पलाइन बनाने के आदेश

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स जसवीर सिंह गढ़ी ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों की शिकायतों और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। स गढ़ी आज यहां पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। पंजाब भवन में हुई समीक्षा बैठक में चेयरमैन स गढ़ी ने पुलिस, स्थानीय सरकारों, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन मामलों का जल्द निपटारा किया जाए ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सके। बैठक के दौरान गढ़ी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक ज़िले में एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए एसपी स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ।

बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले- कहीं कोई झगड़ा नहीं है

नई दिल्ली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ किसी भी मुद्दे पर सलाह दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय भाजपा ही लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संघ का केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के साथ अच्छा समन्वय है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमारा हर सरकार के साथ अच्छा समन्वय है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों, दोनों के साथ हमारा अच्छा समन्वय है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनमें कुछ आंतरिक विरोधाभास हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सामान्य तौर पर व्यवस्था वही है जिसका आविष्कार अंग्रेजों ने किया था ताकि वे शासन कर सकें। इसलिए, हमें कुछ नवाचार करने होंगे। फिर, हम चाहते हैं कि कुछ हो। भले ही कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हमारे लिए पूरी तरह से तैयार हो, उसे यह करना ही होगा और वह जानता है कि इसमें क्या बाधाएँ हैं। वह ऐसा कर भी सकता है और नहीं भी। हमें उसे वह स्वतंत्रता देनी होगी। इसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं है। आरएसएस और भाजपा के बीच मतभेद पर सफाई देते हुए भागवत ने कहा कि इन सब बातों से ऐसा लगता है कि झगड़ा है, लेकिन संघर्ष हो सकता है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, जो हमारे देश की भलाई है।

पीएमजेडीवाई के 11 वर्ष : विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना

जालंधर ब्रीज: वित्तीय समावेश का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने और सामाजिक समानता को प्रोत्साहन देने की इसकी क्षमता में निहित है। वित्तीय समावेश, 2030 के लिए निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से कम से कम 7 को प्राप्त करने के प्रमुख कारकों में से एक है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए सरकार समर्थित वित्तीय समावेश अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कारण है - देश की अत्यधिक विविधता, भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की थी, जो उनके द्वारा घोषित सबसे पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना था, ताकि प्रत्येक परिवार का, विशेष रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के लोगों का, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग लेना सुनिश्चित हो सके। पिछले 11 वर्षों में, पीएमजेडीवाई दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेश कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है, जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों और बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच की सुविधा के बीच की खाई को पाटकर जीवन में बदलाव ला रहा है। आरबीआई के एफआई-सूचकांक का मूल्य मार्च 2017 के 43.4 से बढ़कर मार्च 2025 के लिए 67.0 हो गया है। सूचकांक में वृद्धि वित्तीय समावेश और वित्तीय साक्षरता पहलों के सुदृढ़ होने का संकेत देती है।

पीएमजेडीवाई से पहले, देश के केवल 59% परिवारों और 35% वयस्कों के पास बैंक खाते थे, जबकि योजना के 11 वर्षों के बाद लगभग 100% परिवारों और 90% से अधिक वयस्कों के पास बैंक खाते हैं। अनौपचारिक ऋण प्रणालियाँ, जो गरीबों और वंचित समुदाय के लोगों को कर्ज के चक्र में फँसाती थीं, अब अतीत की बात हो गई हैं।

पीएमजेडीवाई का प्रभाव अभूतपूर्व रहा है। 56.2 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जो मार्च 2015 की तुलना में लगभग 4 गुनी वृद्धि है। इसमें ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 37.5 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 18.7 करोड़ खाते शामिल हैं। इनमें से 56% खाते (लगभग 31.3 करोड़) महिलाओं के हैं। पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है, जो 2015 की तुलना में 17 गुनी वृद्धि है और यह बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। इसने एक ही सप्ताह (23-29 अगस्त, 2014) में 18,096,130 खाते खोलने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें अकेले उद्घाटन के दिन 15 मिलियन खाते खोले गए थे। 16.2 लाख से ज़्यादा बैंक मित्र दूर-दराज़ के इलाकों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाएँ सुलभ हो रही हैं। पीएमजेडीवाई खातों ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सुव्यवस्थित किया है, जिससे सब्सिडी और राहत भुगतान बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। विमुद्रीकरण और कोविड-19 संकट के दौरान, पीएमजेडीवाई खातों ने तेज़ी से वित्तीय सहायता की सुविधा दी, जिससे आर्थिक संकट और महामारी के समय में उनकी उपयोगिता साबित हुई।

एम. नागराजू
(लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं)

2014 में पीएमजेडीवाई की शुरुआत के समय, लगभग 7.5 करोड़ परिवारों के पास बैंक खाते नहीं थे। 2018 में, हमने परिवारों के पास बैंक खाते की सुविधा का उच्चतम स्तर हासिल किया और अपना ध्यान सभी वयस्कों को बैंक खाते की सुविधा देने पर केंद्रित कर दिया। विश्व बैंक की फाइंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के संदर्भ में, खाता स्वामित्व 2014 के 53% से बढ़कर 2024 में 89% हो गया है। भारत में खाता स्वामित्व एशिया में सर्वश्रेष्ठ है और खाता स्वामित्व में पुरुष-महिला अंतर भी नगण्य हो गया है। एनएसएस सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, देश में 94.65% वयस्कों के पास बैंक खाते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर देश के प्रयासों के अनुरूप, इस योजना ने रुपे कार्ड के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है। 38.7 करोड़ से ज़्यादा रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, जो दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस योजना ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं को भी सुविधाजनक बनाया है, जिससे लाखों लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिली है।

अब, सभी गाँवों में से 99.9% में 5 किमी की दूरी के भीतर एक बैंकिंग आउटलेट (शाखा, या बीसी या आईपीपीबी) की सुविधा है। इस विस्तारित बैंकिंग नेटवर्क ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से क्रमशः 2 लाख रुपये के जीवन और दुर्घटना कवर (जन सुरक्षा) का विस्तार करने में मदद की है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिक से अधिक लोग इन जन सुरक्षा योजनाओं में नामांकन करके आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। पीएमजेडीवाई अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और हमारा ध्यान इसके प्रभाव को बनाए रखने और बढ़ाने पर है। सरकार ने वित्तीय समावेश के उच्चतम स्तर को हासिल करने से जुड़े अभियान की शुरुआत की है और बैंक 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक केवाईसी विवरण अद्यतन करने, नए खाते खोलने और सूक्ष्म बीमा एवं पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं। बैंकिंग सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने और निष्क्रियता को रोकने के लिए खाताधारकों को शिक्षित करने पर निरंतर ज़ोर दिया जा रहा है।

हालांकि निष्क्रिय खाते और पुनः केवाईसी आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इस योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव - जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, विश्व बैंक, आईएमएफ आदि द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता दी गयी है, को अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। चूंकि भारत 2025 में पीएमजेडीवाई के 11 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, यह समावेशी शासन की शक्ति का प्रमाण है तथा सार्वभौमिक वित्तीय समावेश प्राप्त करने हेतु विश्व के लिए एक आदर्श है।

सपनों को हकीकत में बदले के लिए फॉलो करें न्यूरोसाइंटिस्ट के ये टिप्स

• जालंधर ब्रीज. फीचर

आजकल सोशल मीडिया पर 'मेनिफेस्टेशन' शब्द काफी ट्रेंड कर रहा है। मेनिफेस्टेशन का मतलब होता है, 'लॉ ऑफ अट्रैक्शन' की मदद से अपनी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में बदलना।

आसान शब्दों से समझे तो इसका मतलब यह है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में घटित हो जाता है। लेकिन सवाल यह यह है कि क्या वाकई ऐसा संभव है। न्यूरोसाइंटिस्ट और पूर्व चिकित्सक डॉ. तारा स्वार्ट सवाल के जवाब में कहती हैं हां। 'द मॉर्निंग' को दिए एक इंटरव्यू में डॉ. स्वार्ट, कहती हैं कि मेनिफेस्टेशन सिर्फ आपकी एक इच्छा नहीं है बल्कि यह तो आपके मस्तिष्क को एक बार फिर आपके लक्ष्यों के अनुरूप ढालने से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं ऐसे न्यूरोसाइंटिस्ट के सुझाए हुए टिप्स, जिनकी मदद से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।

स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें

अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत स्पष्टता से करें। इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप वास्तव में खुद के लिए क्या चाहते हैं। ऐसा करते समय सामाजिक अपेक्षाओं की जगह अपने दिल में छिपी इच्छाओं पर ध्यान दें। अपनी सभी ख्वाहिशों को एक कागज पर उतारकर खुद से सवाल करें कि अगर सफलता की गारंटी हो, तो मैं ये सभी चीजें वाकई हासिल करना चाहूंगा? उदाहरण के लिए 'मैं एक सफल व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं' जैसे अस्पष्ट लक्ष्य की जगह 'मैं एक साल में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहता हूं', ऐसा कुछ लिखें।

सपने ही नहीं मेहनत भी करें

सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं। अपने सपने को पूरा करने के लिए रोजाना कम से कम एक कदम जरूर बढ़ाएं। इसके लिए खुद को ऐसे वातावरण, लोगों और आदतों के बीच रखने की कोशिश करें, जो आपको आपका सपना पूरा करने में मदद कर सकती हैं।

सकारात्मक मानसिकता अपनाएं

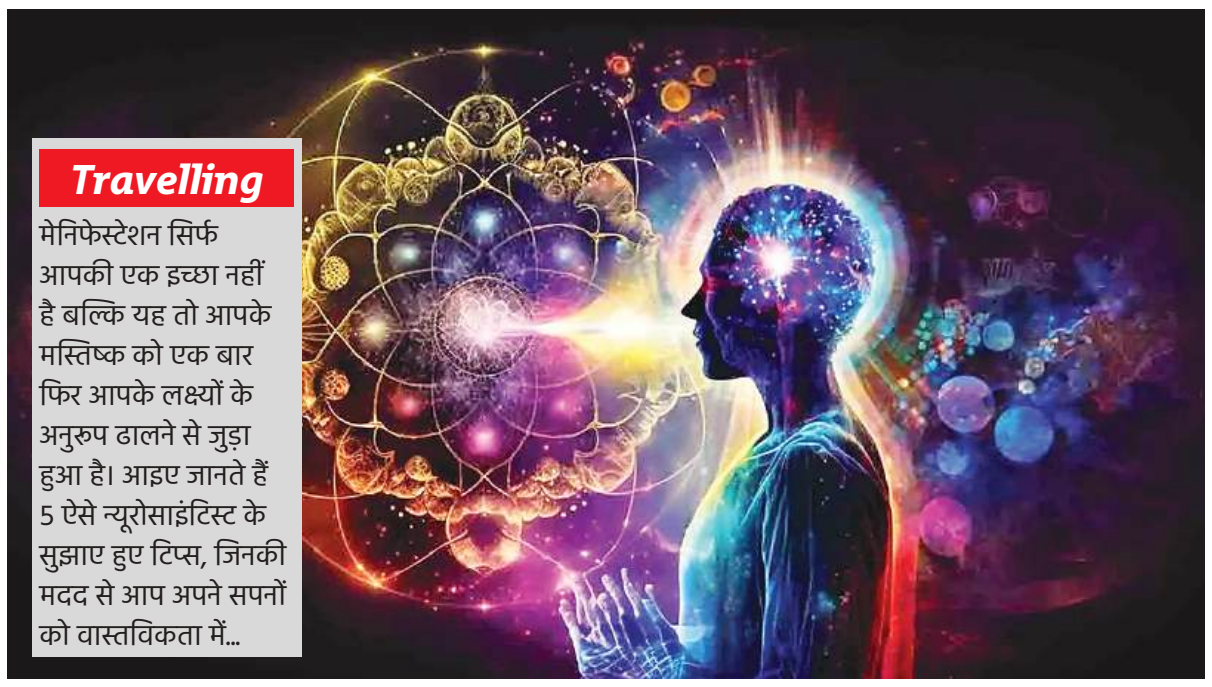

Travelling

मेनिफेस्टेशन सिर्फ आपकी एक इच्छा नहीं है बल्कि यह तो आपके मस्तिष्क को एक बार फिर आपके लक्ष्यों के अनुरूप ढालने से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं 5 ऐसे न्यूरोसाइंटिस्ट के सुझाए हुए टिप्स, जिनकी मदद से आप अपने सपनों को वास्तविकता में...

व्यक्ति का दिमाग उसे हर खतरे से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसा करते समय वह व्यक्ति को किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचने का संदेश देता है। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको यह सोचना होगा कि क्या वास्तव में आपके लिए यह जोखिम उठाना सुरक्षित है या नहीं। अपने सपनों से जुड़े सभी डर और शंकाओं को सकारात्मक सोच और आत्म-विश्वास की मदद से दूर करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को उन अवसरों के लिए तैयार करें जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। ऐसा करते समय बाधाओं की जगह अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें।

एक्शन बोर्ड बनाएं

सपनों को हकीकत बनाने के लिए विजन बोर्ड की जगह एक्शन बोर्ड बनाएं। यह बोर्ड न केवल आपके सपनों को स्पष्ट करेगा, बल्कि उन कोशिशों के बारे में भी आपका नजरिया साफ करेगा जो आपको अपना सना हासिल करने के लिए उठाने होंगे। उदाहरण के लिए अगर आपका सपना एक नया घर खरीदना है, तो बोर्ड पर उस घर की तस्वीर, बजट योजना, और बचत के लक्ष्य शामिल करें।

सफलता के लिए पॉजिटिव बने रहे

सफलता हासिल करने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच और बातें करें। व्यक्ति को नकारात्मक विचार जल्दी घेर सकते हैं। ऐसे में आप अपने घर के हर कोने में पॉजिटिव कोट्स चिपकाकर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए- 'मैं शक्तिशाली हूं,' 'मैं साहसी हूं,' 'मैं एक सुपरस्टार हूं', जैसे विचार अपने शीशे, फोन या ऑफिस की टेबल पर चिपकाकर रखें और रोजाना इन्हें पूरे विश्वास के साथ दोहराएं।

DIET TIPS

उम्र के अनुसार हो बच्चों का आहार बच्चे के खानपान लाएं बदलाव

बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसकी पोषण संबंधी जरूरतें भी तो बदलेंगी! अपने बढ़ते बच्चे के खानपान में किस तरह के बदलाव लाएं, ताकि उसकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें, बता रही हैं एक्सपर्ट...

• जालंधर ब्रीज . फीचर

विकसित होते बच्चों के लिए पोषण बहुत जरूरी है। स्तनपान से लेकर किशोरावस्था तक का उनका सफर इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी बदलती जरूरतों के अनुसार, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा था या नहीं। कुपोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनता है। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल, फरीदाबाद में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेश महाजन के अनुसार, 'माता-पिता के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों की सेहत का उस समय खास ध्यान रखें, जब बच्चों की समझ विकसित न हुई हो। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि विभिन्न आयु समूहों में पोषण संबंधी जरूरतें काफी भिन्न होती हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक बदलाव के अनुरूप होती हैं।'

शिशु के लिए जरूरी है स्तनपान : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छह महीनों तक के बच्चे को सिर्फ मां का दूध दिए जाने की सिफारिश की है। छह से 12 महीने के शिशु को बहुत सारे पोषक तत्वों जैसे मिनरल्स और विटामिन्स की आवश्यकता होती है। इस दौरान उन्हें फॉर्मूला मिल्क और खाने-पीने की दूसरी चीजों के साथ स्तनपान करवाना जरूरी होता है। शिशु को इस उम्र में निम्न पोषक तत्वों की दरकार होती है:

- विकास के लिए प्रोटीन
- मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए स्वस्थ वसा
- हड्डियों के विकास के लिए विटामिन-डी और कैल्शियम
- लगभग छह महीने की उम्र के शिशुओं को ठोस आहार, मसले हुए फल व सब्जियां और आयरन-युक्त अनाज देना शुरू करें।

खाने से करवाएं इनकी दोस्ती : एक से तीन साल के बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतें उनके विकास और ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर होती हैं। इस उम्र में, बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1,000 से 1,400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तीन साल की उम्र तक बच्चे काफी कुछ खाने लगते हैं और धीरे-धीरे उनकी खानपान की आदतें विकसित होने लगती हैं। **किशोर को चाहिए भरपूर पोषण :** किशोरावस्था यानी 13 से 18 वर्ष की इस उम्र तक आते-आते बच्चे मानसिक रूप से इतने विकसित हो चुके होते हैं कि उन्हें सही खानपान और पोषण के महत्व को समझाया जा सकता है। इस उम्र में पोषण संबंधी जरूरतें तीव्र शारीरिक विकास के कारण बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस दौरान, किशोरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में हों।

- इस उम्र में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन-डी आवश्यक है
- इस उम्र में लड़कियों को पीरियड शुरू हो चुका होता है, साथ ही उनकी आयरन संबंधी जरूरतों में भी इजाफा हो जाता है।
- इन्हें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी चाहिए, जो मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि में सहायक होता है।

प्री-स्कूल की तैयारी : चार से पांच साल की उम्र में बच्चा ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसे में ख्याल रखा जाए कि उसे खाने में ऐसे पोषक तत्व मिलते रहें, जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हों। चार से पांच साल के बच्चों का शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है। उनके लिए माइक्रो और मैक्रोन्युट्रिएंट्स, दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। · प्रोटीन के लिए उनके आहार में लीन मीट, अंडे, फलियां और दूध को शामिल करें। · उचित पाचन के लिए फाइबर जरूरी है। इसके लिए सब्जी, फल और साबुत अनाज को उसके नियमित आहार का हिस्सा बनाएं। · विटामिन-डी से समझौता नहीं करें। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए यह जरूरी है।

स्कूल चले हम : स्कूल जाने वाले छह से बारह साल के बच्चों के लिए स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता जरूरी है, ताकि उनके शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। · बढ़ती लड़कियों के लिए इस उम्र में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत जरूरी है। अनार, काला चना आदि आयरन के अच्छे स्रोत हैं।

बच्चों के लिए कितना पानी जरूरी : मानव शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है। शरीर की अनगिनत क्रियाएं पानी पर ही निर्भर करती हैं। हर उम्र में शरीर को अलग-अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है। 0-6 माह तक के शिशुओं को मां के दूध या फॉर्मूला मिल्क से ही पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ मिल जाता है, उन्हें आमतौर पर पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती है। • 6-9 माह: 100 मिलीलीटर 9-12 माह:100-200 मिलीलीटर • 1-3 साल: 800-1000 मिलीलीटर 4-8 साल: 1100-1200 मिलीलीटर • 19-13 साल:1600-1900 मिलीलीटर 14-18 साल: 1900-2600 मिलीलीटर

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

ब्रेकफास्ट में आसानी से बना सकती हैं सूजी का चीला, नोट कर लें रेसिपी

ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अगर पहले से तैयारी ना की हो तो सबह के समय काफी जल्दीबाजी हो जाती है। इस जल्दीबाजी में आप फटाफट से सूजी के चीले की रेसिपी को ट्राई करें। जिसे बनाना बहुत आसान है और ये हेल्दी भी होते हैं।

• जालंधर ब्रीज. रेसिपी

दिनभर की भागदौड़ के बाद कई बार अगले सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी करना हम भूल जाते हैं। ऐसे में दिन की शुरुआत से पहले ही ये ख्याल आता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। ऐसा क्या जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। साथ ही बच्चे-बड़े सब चाव से झटपट खा लें। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सूजी का चीला बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को चीज स्प्रेड कर तो बड़ों को केवल हरी चटनी के साथ सर्व करें। इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है खाने में, तो चलिए जानें कैसे बनाएंगी फटाफट बन जाने वाला सूजी का चीला।

सूजी का चीला बनाने की सामग्री

- एक कप महीन सूजी
- एक कप पानी
- बारीक कटा एक प्याज
- एक से दो हरी मिर्च
- बारीक का अदरक
- धनिया के पत्ते
- एक चौथाई चम्मच अजवाइन
- लाल मिर्च चुटकीभर
- हल्दी पाउडर और
- नमक स्वादानुसार

सूजी का चीला बनाने की रेसिपी

- सबसे पहले महीन सूजी को चालकर रख लें।
- अब उसमे पानी मिला दें और करीब आधे घंटे के लिए ढंककर छोड़ दें। जिससे कि सूजी पानी को सोखकर सॉफ्ट हो जाए।
- इस बीच प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया को धोकर अच्छी तरह से बारीक कैट लें। हरी मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार लें।
- इन चीजों को सूजी के मिक्सचर में डालकर मिक्स कर लें।
- साथ ही कुछ मसाले जैसे अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को भी डाल दें।
- अब इस मिक्सचर को आधा घंटा बीत गया तो इसमे लगभग एक चौथाई कप पानी और डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।
- ध्यान रहे कि सूजी का बैटर मीडियम थिक कंसिस्टेंसी में हो।
- अब पैन को गर्म करें और तेल डालें।
- पैन के गर्म होते ही सूजी के बैटर को पैन में डालें और ध्यान रहे कि इसे ज्यादा फैलाने की जरूरत नही है।
- बस सूजी का घोल इतना गाढ़ा हो कि ये थोड़ा सा फैल जाए और हल्का सा फैलाना पड़े।
- धीमी आंच पर चीले को ढंक दें, जिससे कि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए।
- धीरे से पलट दें और थोड़ी देर और सेंके। बस रेडी है सूजी का चीला।
- चीला वन साइड से जब पक जाए तो उस पर चीज, मिक्सड हर्ब्स वगैरह भी डाल सकती हैं। साथ ही इसे पलटने से अवॉएड करें।

खाने में शामिल करें करी पत्ता, जानिए ऐसा करने के कारण

जालंधर ब्रीज (फीचर) . करी पत्ता की खुशबूदार पत्तियां खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती हैं। ये छोटे गहरे हरे रंग के पत्ते आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, बी, सी और ई जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ-साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन पत्तियों के खूब फायदे होने के बावजूद भी कुछ लोग इसे खाने से कतराते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर करी पत्ते कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम कड़ी पत्ता को खाने में शामिल करने के कारण बता रहे हैं।

1) पाचन में मददार- करी पत्ते में पाचक एंजाइम होते हैं जो खाने को तोड़ने और पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं। इन पत्तों की वजह से खाने को अच्छे से पचाने में मदद मिलती है। पत्तों में मौजूद गुण कब्ज को रोकते हैं और हेल्दी आंत को बढ़ावा देते हैं।

2) वजन मैनेज करने में मदद- करी पत्ते शरीर से फैट और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। ये पेट और चेहरे के आसपास जमा चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। ये पत्ते कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं, जो वजन घटाने के लक्ष्यों के लिए फायदेमंद है।

3) हार्ट हेल्थ- करी पत्ते खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे का कारण बनते हैं। ये पत्ते ब्लड फ्लो में सुधार कर सकते हैं और दिल के काम को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। करी पत्ते का अर्क कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकता है जिससे हार्ट हेल्थ बूस्ट करने में मदद मिलती है।

4) इम्यूनिटी होती है बूस्ट- विटामिन सी, एल्कलॉइड और फेनोलिक से भरपूर करी पत्ते इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये शरीर को संक्रमण और सूजन से बचाते हैं।

5) आंखों की हेल्थ में सुधार- करी पत्ते विटामिन ए और कैरोटीनॉयड का स्रोत हैं, जो अच्छी नजर बनाए रखने और रतौंधी, मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।

6) लिवर हेल्थ में मददगार- करी पत्ते लिवर को ऑक्सीडेटिव तनाव और टॉक्सिन के जमाव से बचाने में मदद करते हैं। ये लिवर के काम को बढ़ावा देते हैं और टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

क्या होगा अगर रोज पंपकिन सीड्स खाने लगे, शरीर में दिखते हैं ये अंतर

• जालंधर ब्रीज. हेल्थ केयर

Health

हेल्दी रहना चाहते हैं तो पंपकिन सीड्स को रोजाना खाना शुरू कर दें। गट एंड थायराइड के डॉक्टर ने रोजाना पंपकिन सीड्स की तय मात्रा खाने के फायदे गिनाएं हैं। जो महिला और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है।

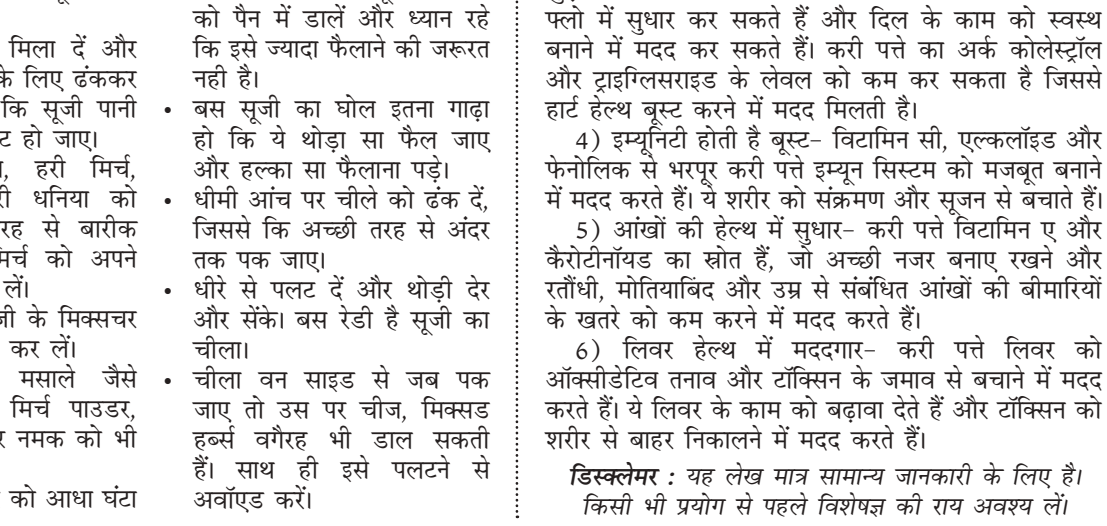

हेल्दी रहना है तो नट्स एंड सीड्स को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। पंपकिन सीड्स को डाइट में शामिल करने के बारे में काफी बार सुना होगा। लेकिन अगर अभी तक आप इस मल्टीन्यूट्रिशन से भरपूर सीड्स को नहीं खाते हैं। तो जरा इसके फायदे जान लें। थायराइड, गट और पीसीओएस जैसी बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर एड्रियन ने रोजाना पंपकिन सीड्स को खाने के फायदे के बारे में बताया है। जानें हर रोज अगर कद्दू के बीज खा लिए तो क्या होगा शरीर पर असर।

हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है - अगर आप हर दिन एक चम्मच के करीब पंपकिन सीड्स खाते हैं तो हेल्दी हार्मोंस को बैलेंस करके रखने में मदद करेगी। सबसे खास बात कि ये महिला और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे ही फायदेमंद है। पंपकिन सीड्स में जिंक, मैग्नीशियम और हैल्दी फैट्स होते हैं जो हार्मोंस को रेगुलट करने में मदद करते हैं।

वजन को कंट्रोल में रखता है - पंपकिन सीड्स के एक चम्मच अगर रोजाना खाए जाएं तो ये वजन को मैनेज करने में मदद करता है। दरअसल, पंपकिन सीड्स में फाइबर और नेचुरल फैट होता है। जिसकी वजह से इसे खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है।

नेचुरल स्लीप में मददगार - जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उन्हें डाइट में एक चम्मच पंपकिन सीड्स जरूर खाना चाहिए। इसमे मौजूद ट्रीपोटॉफोन और मैग्नीशियम नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। जिससे नींद की क्वालिटी में सुधार होता है।

डाइजेशन में मदद - अगर पंपकिन सीड्स की मात्र एक चम्मच मात्रा रोजाना खा ली जाए तो इसमे मौजद हेल्दी फैट स्टूल को सॉफ्ट करने और फाइबर गट लाइनिंग के साथ ही कब्ज को दूर करने में मदद करता है।

शरीर को मिलते हैं जरूरी मिनरल्स - पंपकिन सीड्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ढेर सारे होते हैं। मैग्नीनिशयम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करते हैं। जिससे एनर्जी बनी रहती है।

भिगोकर खाएं पंपकिन सीड्स - पंपकिन सीड्स के फायदों को लेना चाहते हैं तो इन्हें भिगोकर रख दें उसके बाद खाएं। ऐसा करने से पंपकिन सीड्स में मौजूद पोषक तत्वों के अब्जार्शन के चांस बढ़ जाते हैं।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

अमित शाह ने ANI के इंटरव्यू में 130वें संविधान संशोधन विधेयक सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में 130वें संविधान संशोधन विधेयक सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, वे जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। 130वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें ज़मानत नहीं मिलती है तो उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे अपने आप कानूनन पदमुक्त हो जाएंगे। शाह ने कहा कि संसद में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक या संविधान संशोधन लाए, उसे सदन के सामने रखने में विपक्ष का कोई विरोध नहीं होना चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि उन्होंने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया था कि इस संविधान संसोधन को दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए और जब इस पर मतदान हो तो सब दल इस पर अपना मत दे सकते हैं। शाह ने कहा कि सरकार के किसी भी विधेयक या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और विपक्ष का इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की संसद के दोनों सदन बहस और चर्चा के लिए हैं न कि शोरगुल और हंगामे के लिए। गृह मंत्री ने कहा कि बिल को पेश न होने देने की यह मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह बिल सिर्फ विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह कहकर कि सरकार के लोगों के खिलाफ FIR नहीं होती है, जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है और अगर फर्जी केस होगा तो देश की अदालतें आंखें मूंद कर नहीं बैठेंगी। शाह ने कहा कि किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है और अगर ज़मानत नहीं मिलती है तो पद छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल में रह कर सरकार चला सकता है। क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए शोभनीय है। उन्होंने कहा कि अगर 30 दिन के बाद ज़मानत मिल जाती है तो वे फिर शपथ ले सकते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जेल में डालने का प्रावधान हमारी सरकार ने नहीं बनाया वह सालों से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि 130वें संविधान संशोधन में गंभीर अपराध की व्याख्या की गई है कि जहां 5 साल से अधिक सज़ा का प्रावधान है वहां पद छोड़ना होगा। जिन पर भ्रष्टाचार या 5 साल से अधिक सज़ा वाले अपराध के आरोप हैं, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाएं, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व

कानून में प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को दो साल या अधिक की सज़ा होती है तो वह सांसद के रूप में अपने स्थान से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोरल ग्राउंड तय करने के लिए यह कानून आज़ादी के समय से बना हुआ है। शाह ने कहा कि कई लोगों की सदस्यता समाप्त हुई और तुरंत रिवाइव भी हुई।

अमित शाह ने कहा कि आज़ादी से अब तक कई नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जेल गए। लेकिन अब यह ट्रेंड शुरू हुआ है कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार के सचिव, DGP, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर चिंता और चर्चा होनी चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अपने आप को इस संविधान संशोधन के तहत रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल की तत्कालीन प्रधानमंत्री 39वां संविधान संशोधन लेकर आई थीं जिसमें उन्होंने खुद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ मुकदमों के दायरे से बाहर रखा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी जेल जाएगा तो उसे इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में कोर्ट में कोई देरी नहीं होगी क्योंकि कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना होगा। इससे फैसला जल्दी होगा क्योंकि हमारी अदालतें भी कानून की गंभीरता को समझती हैं।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत स्पष्ट रूप से यह मानना है कि देश में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि जब संविधान बना था तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल जाएगा और फिर भी मुख्यमंत्री बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने नैतिक मूल्यों के स्तर को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। यह कानून नैतिक मूल्यों के स्तर को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मज़बूत होगा। उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें संवेदनशील हैं और जब किसी का पद जाता है तब निश्चित रूप से वे समयसीमा के तहत ज़मानत पर फैसला देगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल को वेंडेटा की बात करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार के समय में कम से कम 12 मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद सीबाई की जांच हुई और बहुत सारे लोग फंसे। उन्होंने कहा कि अगर जेपीसी बनाने का निर्णय होने के बाद भी कोई पार्टी इसका बहिष्कार करती है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। शाह ने कहा कि यह बिल महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों के सदस्यों से मशविरा करने के बाद एक कंसीडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को बात रखने का मौका देती है लेकिन अगर विपक्ष अपनी बात रखना ही नहीं चाहता तो देश की जनता भी यह सब देख रही है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार में गरदन तक डूबा है तो फिर वह अरेस्ट भी होगा, जेल भी जाना पड़ेगा और इस्तीफा भी देना होगा। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष उन्हें नैतिकता के पाठ न पढ़ाए। शाह ने कहा कि जब उन पर आरोप लगा था और सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था, तब उन्होंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। केस चला और उसमें जजमेंट भी आया कि वे पूर्णतया निर्दोष थे। उन्होंने कहा कि उस जजमेंट में कहा गया था कि ये कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है और उनका दूर दूर तक इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शाह ने कहा कि उन्हें शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था बल्कि उनके खिलाफ केस खारिज किया गया था। शाह ने कहा कि उन्हें 96वें दिन ज़मानत मिल गई थी लेकिन तब भी वे दोबारा शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बने। इतना ही नहीं, जब तक उन पर लगे सारे आरोप खारिज नहीं हो गए तब तक उन्होंने किसी भी संवैधानिक पद की शपथ नहीं ली थी।

अमित शाह ने कहा कि नैतिकता का स्तर चुनावी जय-पराजय के साथ नहीं जुड़ा बल्कि वह सूर्य और चंद्रमा की तरह हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। उन्होंने कहा कि इस कानून से हमारे सभी साथी दल पूरी तरह से सहमत हैं। शाह ने कहा कि सिर्फ सत्ता पक्ष तय नहीं करता कि संसद किस प्रकार चलनी चाहिए। किसी भी बिल या संविधान संशोधन के लिए अगर विपक्ष स्वस्थ वातावरण नहीं बनाता है तो देश की जनता यह सब देख रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बिल पारित हो जाएगा और विपक्ष में कई लोग ऐसे होंगे जो नैतिकता के आधार पर इसका समर्थन करेंगे।

55 लाख राशन कार्ड धारकों को हटाने संबंधी दावा पूरी तरह भ्रामक : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से 55 लाख राशन कार्ड धारकों को हटाने संबंधी दावा पूरी तरह भ्रामक हैं और इनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत पंजाब की 1.41 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों में किसी भी लाभार्थी को नहीं हटाया गया है और खाद्यान्न का आवंटन निरंतर जारी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप है और केंद्र सरकार ने केवल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने हेतु कहा है। पंजाब को मार्च 2023 में ई-केवाईसी शुरू करने की सलाह दी गई थी तथा सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा तीन बार बढ़ाई गई। बावजूद इसके, केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए खाद्यान्न आवंटन बंद नहीं किया है।

उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी की अंतिम समय सीमा 30 जून, 2025 थी,

फिर भी पंजाब के लिए खाद्यान्न आवंटन जारी है। जून से अगस्त 2025 के बीच राज्य को लगभग 1.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 10% लाभार्थियों, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं किया है, को भी मुफ्त खाद्यान्न आवंटन जारी रहेगा, क्योंकि पंजाब की समग्र एनएफएसए सीमा में कोई कमी नहीं की गई है। अब तक पंजाब ने लगभग 90% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी कर ली है। हालांकि, राज्य के राशन कार्ड डेटाबेस में गंभीर विसंगतियाँ पाई गई हैं और लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को दोबारा से सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया है। जोशी ने जोर देकर कहा कि एनएफएसए, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। केंद्र ने पंजाब की सीमा से एक भी लाभार्थी को कम नहीं किया है और स्थापित मानकों के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करना जारी रखा है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार का यह दायित्व है कि वह वास्तविक पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करे और खाद्यान्न की लीकेज व अवैध आवाजाही को रोके, ताकि केवल वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह निहित स्वार्थी समूहों के दबाव में आकर केंद्र पर निराधार आरोप लगाने के बजाय खाद्यान्न की अवैध आवाजाही और हेरफेर के विरुद्ध कार्रवाई करे।

वॉटरशेड : साकार होता विकसित भारत का सपना,जल और मिट्टी संरक्षण से कृषि और किसान समृद्धि की ओर

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

जल ही जीवन है और मिट्टी हमारा अस्तित्व, हमारा आधार है। जल और मिट्टी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जब पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं, नदियों की धाराएं कमजोर हो रही हैं और भूजल पाताल में समा रहा है, तब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल और मिट्टी की रक्षा करें। जब हमारे खेत हरे-भरे होंगे और किसान खुशहाल होंगे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार किया जा सकेगा, क्योंकि इस संकल्प का रास्ता हमारे गांवों की पगडंडियों, उपजाऊ मिट्टी और लहलहाती फसलों से होकर ही गुजरता है।

आज बिगड़ते पर्यावरण के कई जगहों पर भूजल का स्तर हजार-डेढ़ हजार फीट नीचे चला गया है। अगर हमारी उपजाऊ मिट्टी इसी तरह बहती रही और जमीन बंजर होती रही, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा? इसी दूरदर्शी सोच और भविष्य की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा दूरदृष्टि से काम किया है। वे सिर्फ आज की नहीं, आने वाले 50-100 वर्षों की सोचते हैं। उनके नेतृत्व में भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग, 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत 'वॉटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY)' को पूरे देश में लागू कर रहा है। लेकिन यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। इस महायज्ञ में सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। यह धरती को बचाने का अभियान है। पानी, माटी, धरती बचेगी तो भविष्य बचेगा। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जो सूखे और वर्षा पर निर्भर हैं और इन इलाकों में बसे हमारे किसान भाई-बहनों के जीवन में समृद्धि लाने का एक महाभियान है, जहाँ कभी पानी की एक-एक बूँद के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर यह वाटरशेड योजना है क्या? मैं उन्हें सरल भाषा में बताता हूँ कि यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि लोगों की अपनी, लोगों के लिए चलाई जाने वाली एक क्रांति है। इस योजना का मूलमंत्र है- "खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में"। इसके तहत हम सब मिलकर खेतों की मेड़ें मजबूत करते हैं, खेत में ही छोटे तालाब बनाते हैं, और छोटे-छोटे नालों पर चेक डैम जैसी जल-संरचनाएं खड़ी करते हैं। इससे बारिश का पानी बहकर बेकार नहीं जाता, बल्कि धीरे-धीरे धरती की प्यास बुझाता है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है और मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है।

इस योजना की सबसे बड़ी शक्ति इसकी जन-भागीदारी है। गाँव के लोग खुद बैठकर यह तय करते हैं कि तालाब कहाँ खोदना है, मेड़ कहाँ बनानी है और पेड़ कहाँ लगाने हैं। भूमिहीन परिवारों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी मुर्गीपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस

शिवराज सिंह चौहान
(लेखक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है)

योजना के बहुत सुखद परिणाम मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान भाई-बहनों को मिला है, जिनकी आमदनी में 8% से लेकर 70% तक की ठोस वृद्धि हुई है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 2015 से अब तक, सरकार ने ₹20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करके देशभर में 6,382 से अधिक परियोजनाएं चलाई हैं और लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का काम किया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहाँ कभी सूखा एक बड़ी समस्या थी, आज आदिवासी गाँवों में पानी भरपूर है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ गई है। परियोजना क्षेत्र के 22 गाँवों में भूजल स्तर एक मीटर तक बढ़ गया है। इससे खेती में भी परिवर्तन आया है। यहीं के किसान भाई बताते हैं कि गाँव में चेकडैम बनने से अब वे मक्के के साथ-साथ चने की फसल भी ले रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी ₹50,000 से ₹60,000 तक बढ़ गई है। साथ ही झाबुआ की ही परवलिया पंचायत में 12 खेतों में बने खेत तालाबों से किसानों की आमदनी ₹1 लाख से ₹1.5 लाख प्रति हेक्टेयर तक बढ़ी है।

इस योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा चेक डैम, रिसाव तालाब, खेत तालाब, जैसी वाटरशेड संरचनाएँ बनी हैं। 5.6 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस उपलब्ध हुए हैं, जिससे ग्रामीण रोज़गार में वृद्धि हुई है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लागू होने से गाँवों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। जहाँ पहले पानी की कमी थी, उन परियोजना क्षेत्र में अब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा नए इलाक़े में जल स्रोत फैले हैं, यानी 16% का इज़ाफा हुआ है। साथ ही अब किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों और अन्य पेड़-पौधों की खेती भी करने लगे हैं, जिससे बागवानी और पेड़-पौधों की खेती का दायरा 12% बढ़कर 1.9 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है।

राजस्थान के बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ पानी की कमी किसानों को पलायन पर मजबूर कर रही थी, आज अनार की खेती से हरियाली लौट आई है। योजना के अंतर्गत 120 से अधिक किसानों को अनार के पौधे उपलब्ध कराए गए, जो वहाँ की बालू मिट्टी और सीमित पानी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से पनप जाते हैं। अनार की खेती ने न केवल आमदनी बढ़ाई, बल्कि बूड़ीवाड़ा गांव के मांगीलाल परांगी का कहना है कि उनके जैसे किसान अब अरंडी छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ गए हैं। त्रिपुरा के दाशी रियांग और बिमन रियांग जैसे किसान योजना की मदद से अनानास की बागवानी करके अपनी बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बना रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

इस पूरी क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने और इसे एक जन-आंदोलन बनाने के लिए हमने 'वॉटरशेड यात्रा' भी निकाली। इस यात्रा के माध्यम से हमने देशभर में जल संरक्षण और भूमि संवर्धन के लिए एक जनजागरण अभियान चलाया। हमने इस योजना में तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया है। 'भुवन जियोपोर्टल (सृष्टि)' और 'दृष्टि' मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों से योजनाओं की प्रगति की सटीक निगरानी हो रही है। किसानों की मेहनत और हमारी योजनाओं की वजह से, देशभर के फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। सैटेलाइट से मिले आँकड़े बताते हैं कि फसल क्षेत्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर (5% की वृद्धि) और जल स्रोतों के क्षेत्र में 1.5 लाख हेक्टेयर (16% की वृद्धि) का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8.4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बंजर जमीन अब फिर से खेती के योग्य बन चुकी है।

"सिंधु की पुकार : संप्रभुता की वापसी और गौरव की बहाली"

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

मानसून शब्द पूरे भारत में खुशी और गर्व का संचार करता है। यह नवाचार, नवीनीकरण और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को तत्काल गति प्रदान करने का प्रतीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर वर्षा के साथ मिलकर, इसकी नदियों को पुनर्जीवित करती है और देशभर में जल संसाधनों का विस्तार करती है। यह प्रगति के मौसम का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के साथ मिला दिए जाने पर देशभक्ति की एक अनूठी भावना का संचार करता है। लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर आकांक्षी नागरिकों के लिए एक ऐसा खाका पेश किया जो एक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

अर्जुन राम मेघवाल
(केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री, भारत सरकार)

संसद के इस विशेष मानसून सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने इसे भारत का गौरवशाली सत्र बताया था। भारतीय सैनिकों का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारखानों पर निर्णायक प्रहार और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का स्थगन—ये सब भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के सबूत हैं और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। फिर भी, सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के बावजूद, विपक्ष ने बाधा डालने का रास्ता चुना और व्यापक जनहित की कीमत पर विचार-विमर्श को राजनीतिक नौटंकी में सीमित कर दिया।

देश अरसे से स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने की कांग्रेस की पुरानी आदत का बोझ ढोता चला आ रहा है। विभाजन की दुखद विभीषिका से लेकर नेहरूवादी कूटनीति की महंगी पड़ने वाली विफलताओं तक, इतिहास गवाह है कि कैसे इन फैसलों ने भारत की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) पर बारीकी से गौर करने पर, जनता और देश के विकास की कीमत पर तुष्टिकरण व अति-उदारता की एक ऐसी कहानी सामने आती है, जिसने राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को निरंतर बाधित किया। यह घोर विडंबनापूर्ण है कि भारत के विकास से जुड़े हितों का त्याग एक ऐसे राजनीतिक आकलन से प्रेरित थे जिसने अपने नागरिकों के कल्याण से ऊपर पाकिस्तान के हितों को तरजीह दी।

मूल रूप से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), सिंधु नदी प्रणाली के जल का आवंटन पाकिस्तान के पक्ष में (80:20) करती है। सिंधु नदी प्रणाली का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे वैसे व्यापक जल संसाधन छिन गए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विशाल शुष्क एवं सूखाग्रस्त इलाकों का कायाकल्प कर सकते थे। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती, तो सुव्यवस्थित जल अवसंरचना इस इलाके के संपूर्ण विकास की तस्वीर को बेहतर बना सकती थी।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण त्याग से व्यापक कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीदें भ्रामक साबित हुईं। इस संधि के प्रक्रियात्मक संचालन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इसे दो महीने बाद, नवंबर में, संसद के समक्ष रखा गया और वह भी मात्र दो घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए। जैसे ही इस संधि से जुड़े तथ्य सामने आए, इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में छपी प्रतिकूल टिप्पणियां सुर्खियों में छायी रहीं। इतने महत्वपूर्ण समझौते के प्रति संसदीय स्तर पर बरते गए इस जल्दबाजी भरे व्यवहार ने लोकतांत्रिक निगरानी, पारदर्शिता और तत्कालीन नेतृत्व की दुर्भावनापूर्ण मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस सीमित संसदीय पड़ताल के बावजूद, सिंधु जल संधि को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक युवा सांसद थे, ने चेताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का यह तर्क बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है कि पाकिस्तान की अनुचित मांगों के आगे झुकने से मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी।

संसद में 30 नवंबर 1960 को हुई बहस से पता चलता है कि सभी दलों ने इस संधि की आलोचना की थी। अधिकांश सदस्यों ने सरकार की आलोचना की थी और उस पर पाकिस्तान के सामने झुकने तथा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राजस्थान से कांग्रेस सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए.सी. गुहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद केटीके तंगमणि, सरदार इकबाल सिंह, बृजराज सिंह ने इस जल कूटनीति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंताएं जाहिर की थी और इसके विफल होने से जुड़े नतीजों के बारे में अंदेशा जताया था। कुल मिलाकर, इस संधि को "एकतरफा, न कि लेन-देन पर आधारित" कहा जा सकता है।

इस संदर्भ में, यह विडंबना ही थी कि लोकसभा में अपने उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने माननीय सांसदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और उन्हें कमतर भी आंका। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संसदों द्वारा की गई आलोचना तथ्य और निहित विचारों से अनजान रहने पर आधारित है। उन्होंने (नेहरू) आगे कहा, "मुझे इस बात का दुख है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को... एक ऐसा मामला जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है... इतने हल्के में और इतनी लापरवाही एवं संकीर्ण सोच के साथ लिया जा रहा है।"

इस संधि ने भारत के हितों को कुंद कर दिया और यह पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक उपलब्धि साबित हुआ। अयूब खान ने एक सार्वजनिक प्रसारण में स्वीकार किया था कि इस संधि की वैधता और गुण-दोष पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन इस मामले में नेहरू की कूटनीतिक विफलता ने पाकिस्तान को बढ़त दिला दी।

नव नियुक्त अध्यक्ष पद्म श्री से सम्मानित प्रो. (डॉ.) बी. के. एस. संजय का एम्स, गुवाहाटी ने किया स्वागत

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गुवाहाटी में एक प्रेरणादायक संवाद सत्र का आयोजन हुआ। जिसमें संस्थान के नव नियुक्त अध्यक्ष, पद्म प्रो. (डॉ.) बी.के.एस. संजय ने शिरकत की। डॉ. संजय एक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें सर्जन, शिक्षाविद, लेखक एवं समाजसेवी के रूप में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है।

डॉ. संजय ने अपनी बुनियादी ऑर्थोपीडिक शिक्षा कानपुर, पीजीआई चंडीगढ़ और सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपीडिक्स, नई दिल्ली से प्राप्त की। उन्होंने स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका और रूस से ऑर्थोपीडिक्स की विभिन्न उप-विशेषज्ञताओं में उन्नत प्रशिक्षण और फैलोशिप भी प्राप्त की हैं। अपने 45 वर्षों के दीर्घ चिकित्सा करियर में उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अशोक पुराणिक ने डॉ. संजय का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉ. संजय का अनुभव और दूरदर्शी नेतृत्व एम्स गुवाहाटी को स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में सशक्त करेगा।

संकाय एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डॉ. संजय ने भारत सरकार का

धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। उन्होंने संस्थान के समग्र विकास हेतु अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने कहा कि एम्स गुवाहाटी को नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाना चाहिए।

पद्म डॉ. संजय ने नवाचार, नैदानिक अनुसंधान तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि पूर्वोत्तर भारत की विशेष स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सके। उन्होंने कैंसर, हृदय रोग, नशा मुक्ति तथा दिव्यांगता को प्रमुख क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं को बताते हुए कहा कि इनके लिए उन्नत उपचार, अनुसंधान और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही।

उन्होंने आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, अमृत औषधि केंद्र, टीकाकरण क्लीनिक (जिसमें पीले बुखार का टीकाकरण शामिल है) और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाओं जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने की आवश्यकता जताई, जिससे एम्स गुवाहाटी को सस्ती, समावेशी एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।

टीम वर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. संजय ने संकाय, रेजिडेंट डॉक्टरों एवं स्टाफ से सेवा भावना, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें भावी चिकित्सकों को करुणाशील, कुशल और संवेदनशील डॉक्टरों के रूप में तैयार करना चाहिए, ताकि एम्स गुवाहाटी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उच्चतम् एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बन सके।

इस अवसर पर संकाय के सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दिखाई और संस्थान की प्रगति में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डॉ. संजय ने संस्थान की अब तक की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि प्रो. (डॉ.) अशोक पुराणिक के नेतृत्व में एम्स गुवाहाटी एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित होगा। सत्र का समापन इस सामूहिक संकल्प के साथ हुआ कि एम्स गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, अपितु पूरे देश की स्वास्थ्य सेवा करने वाला एक अग्रणी संस्थान बनाया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत पहुंचे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, राहत कार्यों का लिया जायजा

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम और तेज करने के आदेश

• **जालंधर ब्रीज.** सुल्तानपुर लोधी

पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बाउपुर और आसपास के गांवों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से जाकर राज्यसभा सांसद संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल के साथ पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ के दौरान किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्यास नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य में और तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दी गई ड्यूटी के तहत वे लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए आए हैं। भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाख वरियांह और मंड कूका के गुरुद्वारा साहिब में राहत कैंपों में लोगों के लिए आवास, दवाइयों, और राशन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। भगत ने ढिलवां के प्रभावित गांव कम्मेवाल के बागूवाल में लोगों को दी जा रही सहायता का भी जायजा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार मेडिकल सहायता दी जा रही है। महिलाओं को सैनिटरी पैड और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अन्य सामग्री का वितरण किया गया है। भगत ने लाख वरियांह में राहत कैंप में लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने कैबिनेट मंत्री को जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन सरबजीत सिंह लुबाना, एसएसपी गौरव तूरा, हलका इंचार्ज एडवोकेट कर्मबीर सिंह चांदी, संगठन इंचार्ज परमिंदर सिंह ढोट, साइंस टेक्नोलॉजी बोर्ड के सदस्य कंवर इकबाल सिंह और अन्य उपस्थित थे।

लगभग 40 पशुओं को सुरक्षित निकाला, 500 से अधिक पशुओं का किया इलाज

सुल्तानपुर लोधी (जालंधर ब्रीज). डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की विभिन्न टीमों के माध्यम से पशुधन की सुरक्षा के लिए निरंतर स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ दवाइयां और पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज 40 से अधिक पशुओं को नावों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लोगों से अपील की कि ब्यास नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण वे अपने पशुधन को प्रशासन की टीमों की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं ताकि पशुधन के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम नंबर 62800-49331, 01822-231990 और सुल्तानपुर लोधी सब डिवीजन का बाढ़ कंट्रोल रूम 01828-222169 24 घंटे कार्यरत हैं। डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग की 6 टीमें 24 घंटे लोगों के पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल के लिए तैनात हैं।

लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी, सेना को बुलाया गया

सुल्तानपुर लोधी (जालंधर ब्रीज). कपूरथला जिले में बाढ़ की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी साझा करते हुए डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने बताया कि हाल की स्थिति में 2 लाख 31 हजार क्यूसेक पानी आ रहा है, जिसके कारण निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग तुरंत प्रशासन द्वारा दिए गए नंबरों पर संपर्क करें ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ब्यास नदी में पानी बढ़ने के मद्देनजर लोगों की जान की रक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी क्षमता के साथ डटा हुआ है। उन्होंने बताया कि एस.डी.आर.एफ. की टीमें 24 घंटे कार्यरत हैं और सुबह से ही लगभग 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की सेवाएं ली गई हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 62800-49331, 01822-231990, सुल्तानपुर लोधी सब डिवीजन के बाढ़ रोकथाम कंट्रोल रूम 01828-222169 और भुलत्थ सब डिवीजन के प्रभावित क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन 01822-271829 पर संपर्क किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में आ जाएं ताकि किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान से बचा जा सके।

कमिश्नरेट पुलिस की ड्रग नेटवर्क के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 19 गिरफ्तार

348.24 ग्राम हेरोइन, 65 नशीली गोलियां और 2 कारें बरामद

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत लगातार जारी अभियान को जारी रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले तीन दिनों में शहर में नशे के खिलाफ विभिन्न अभियान चलाए। इस दौरान 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 348.24 ग्राम हेरोइन, 65 नशीली गोलियां और 2 कारें बरामद की गई।

पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि पिछले तीन दिनों के दौरान, कमिश्नरेट जालंधर के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने सरकारी अधिकारियों की निगरानी में कई संदिग्ध जगहों पर नाकाबंदी और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे की गतिविधियों में शामिल 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एन.डी.पी.एस. के मामले दर्ज किए। 12 मामलों में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 348.24 ग्राम हेरोइन और 65 नशीली गोलियां बरामद की है। इनमें से कुछ आरोपी ऐसे है जो पहले भी नशे के कारोबार में शामिल रहे है।

इस कार्रवाई के दौरान, थाना रामा मंडी में पुलिस टीम द्वारा एक कार (पीबी08डीवी7600) को कब्जे में लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन अभियानों के दौरान, पुलिस टीम ने थाना डिवीजन नंबर 7 में नशे के खिलाफ सफलता हासिल की और एक आरोपी को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके पिछले और अन्य संबंधों की जांच की गई और इस नशे के नेटवर्क से जुड़े 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 281 ग्राम हेरोइन और एक कार (पीबी19-एच-9864) बरामद की गई। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा, कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए भी प्रयास किए जा रहे है, जिसके तहत कुल 17 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है।

मुआवजे की घोषणा में विफल रहने पर बाजवा ने मान पर साधा निशाना

• **जालंधर ब्रीज.** गुरदासपुर

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर राहत प्रदान करने और हाल ही में आई बाढ़ से तबाह हजारों परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने में पूरी तरह से विफल रहने के लिए तीखा हमला किया। बाजवा ने अपने विधानसभा क्षेत्र कादिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी दौरा किया और बाद में बुरी तरह प्रभावित गुरदासपुर तथा दीनानगर क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, डिप्टी सीएलपी अरुणा चौधरी, गुरदासपुर विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहरा और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी भी थे।

यात्राओं के दौरान, बाजवा ने किसानों, दुकानदारों और ग्रामीणों से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी फसलें, पशुधन और घर खो दिए हैं। सरकार की निष्क्रियता पर गुस्सा व्यक्त करते हुए, बाजवा ने कहा: "पंजाब के किसान पूरी तरह से तबाही देख रहे हैं। खेत जलमग्न हैं, घर नष्ट हो गए हैं, और लोगों तक कोई ठोस राहत नहीं पहुंची है। मान साहब कल यहां एक फोटो खिंचवाने से ज्यादा कुछ नहीं के लिए आए थे। वास्तविकता यह है कि उनकी सरकार जमीन से गायब है।बाजवा ने लोगों को याद दिलाया कि आप सरकार ने बाढ़ रोकथाम उपायों और नदियों से गाद निकालने पर 230 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया था, फिर भी गांव अभी भी जलमग्न हैं। उन्होंने कहा, 'अगर इतने लंबे दावों के बाद भी परिवार भूखे और बेघर रह जाते हैं तो मान जी को जवाब देना चाहिए कि वह पैसा कहां गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहत घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वे जमीन पर वास्तविक सहायता में तब्दील न हों.'उन्होंने राहत के संकेत के तौर पर गुरदासपुर में सरकारी हेलीकॉप्टर छोड़ने के मुख्यमंत्री के दावे को भी खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, 'हेलीकॉप्टर पंजाब के लोगों का है, भगवंत मान का नहीं। यह घरों का पुनर्निर्माण या परिवारों को खिला नहीं सकता है। पंजाबियों को अपने मुख्यमंत्री से वित्तीय मुआवजे, पुनर्वास और चिकित्सा सहायता की उम्मीद है, न कि केवल प्रकाशिकी।

सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कवर करने के निर्देश

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). सहकारी संस्थाओं की कार्यवाहियों में भागीदारी बढ़ाने, लागत घटाने और इनके समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं गिरीश दयालन ने राज्यभर की सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकों और कार्यवाहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के ज़रिए कवर करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ संवैधानिक अदालतों द्वारा वीसी मोड के प्रयोग के उपरांत उठाया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से कानूनी समर्थन प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों को मान्यता देता है।

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प उपलब्ध होगा। बोर्डों, समितियों, आम सभाओं/एजीएम और निजी सुनवाईयों की बैठकों के नोटिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक पहुंच के विवरण भी शामिल होंगे। दयालन ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एक वैकल्पिक माध्यम है और यह कोरम, नोटिस या मतदान संबंधी कानूनी आवश्यकताओं में कोई बदलाव नहीं करती।

आईटीआई उन्नयन व उत्कृष्टता केंद्र युवकों के लिए रोज़गार के अवसर खोलेंगे : जयंत चौधरी

चंडीगढ़ में क्षेत्रीय कौशल मंत्रियों का सम्मेलन 'कौशल मंथन' सफलतापूर्वक आयोजित

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में आज चंडीगढ़ में "कौशल मंथन - क्षेत्रीय कौशल मंत्रियों का सम्मेलन" आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय "आईटीआई उन्नयन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना" था। माननीय प्रधानमंत्री के कौशल, पुनर्कौशल और अप-स्किलिंग के मंत्र से प्रेरित होकर, यह सम्मेलन कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, जयंत चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

सम्मेलन में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के कौशल मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, बिहार , राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने हिस्सा लिया।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, "यह सम्मेलन 'कौशल भारत मिशन' को नई दिशा प्रदान करेगा। आईटीआई उन्नयन और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना युवाओं को उद्योग-उन्मुख आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। भारत वैश्विक कौशल अर्थव्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।" उन्होंने आगे बताया कि "2014 में भारत में केवल 600 स्टार्टअप थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारत की युवा शक्ति और कौशल विकास कार्यक्रम मिलकर देश को नवाचार और उद्यमिता के एक नए युग में आगे ले जा रहे हैं।"

138 रेलवे स्टेशनों पर चलाया तलाशी अभियान

● 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के 180वें दिन पंजाब पुलिस ने 84 नशा तस्कर काबू किए; 1.8 किलो हेरोइन बरामद ● नशा छुड़ाने संबंधी प्रयासों के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने 58 व्यक्तियों को नशा छोड़ने का इलाज लेने के लिए राज़ी किया

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

'युद्ध नशों विरुद्ध' को 180वें दिन जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने प्रदेशभर के 138 रेलवे स्टेशनों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया। यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर प्रदेश के सभी 28 जिलों में एक ही समय पर चलाया गया। इस राज्य-स्तरीय कार्रवाई की निजी तौर पर निगरानी कर रहे विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि सभी सीपीज़/एसएसपीज़ को इस कार्रवाई को सफल बनाने के लिए गज़टेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी में भारी पुलिस बल तैनात करने को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 138 रेलवे स्टेशनों पर चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1189 लोगों की जांच की गई। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान 7 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए काबू भी किया गया। इसके अलावा, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए आज 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1.8 किलो हेरोइन, 24 किलो भूक्की और 5400 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इस तरह केवल 180 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 27,508 हो गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिये कहा है।

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 62 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने प्रदेशभर में छापेमारी की, जिसके बाद राज्यभर में 57 एफआईआर दर्ज की गईं हैं। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति - एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) - लागू की है।

भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के बड़े भाई का निधन

जालंधर (जालंधर ब्रीज). भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के बड़े भाई राम प्रसाद शर्मा (आयु 63 वर्ष) का आज पी.जी.आई. चंडीगढ़ में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राम प्रसाद शर्मा जी के निधन की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

राम प्रसाद शर्मा जी का अंतिम संस्कार 29 अगस्त को प्रातः 11 बजे पठानकोट स्थित सिविल अस्पताल के पास वाले शमशान घाट में किया जाएगा। गौरतलब है कि अश्वनी शर्मा जी कल ही 27 अगस्त 2025 को भाजपा के वरिष्ठ नेता एनके वर्मा के बड़े भाई बिमल किशोर वर्मा जी के अंतिम संस्कार में चंडीगढ़ में शामिल हुए थे।

पंजाब सरकार की ई-गवर्नेंस में बड़ी पहल: शहरी नागरिकों के लिए शुरू होंगी 8 नई

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत 8 नई सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारू बनाना, पारदर्शिता को बढ़ाना और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने नई सेवाओं के मुख्य बिंदु साझा करते हुए बताया कि शहरी निवासियों के लिए पालतू जानवरों के लाइसेंसों की ऑनलाइन आवेदन और जारी करने की सुविधा, किराये और लीज़ समझौतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म, विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए ऑनलाइन अनुमतियां, यातायात और अन्य उल्लंघनों के लिए ई-चालान प्रणाली, और नागरिकों के लिए कूड़ा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान जैसी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा, "पंजाब पहले से ही ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी राज्य है और इन नई पहलकदमियों का उद्देश्य शहरी सेवाओं को अगले स्तर पर ले जाना है।" उन्होंने बताया कि "ये 8 नई सेवाएं न केवल हमारी स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता में सुधार लाएंगी बल्कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक सुविधाजनक और पारदर्शी पहुँच भी प्रदान करेंगी।"

द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास

स्पोर्ट्स डेस्क. भारतीय क्रिकेट में एक और युग का अंत हो गया है। दरअसल, महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। चेतेश्वर पुजारा न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि प्रोफेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको अब खेलते हुए नहीं दिखेंगे। पुजारा ने आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भारत के लिए 2023 में खेला था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल था।

दाएं हाथ के बल्लेबाज पुजारा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा कि, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना- इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन जैसा कि कहते हैं हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है और यही हो गया है। अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।

37 वर्षीय पुजारा ने अपने रिटायरमेंट नोट में लिखा कि, एक छोटे से शहर राजकोट का बच्चा होकर मैं अपने माता-पिता के साथ सितारों को छूने का सपना लेकर निकला था और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब देखा था। तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये खेल मुझे इतना कुछ देगा- अनमोल अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका।

पुजारा ने आगे लिखा कि, मैं बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ का दिल से आभारी हूं। जिन्होंने मेरे करियर में मुझे अवसर और सहयोग दिया।

पंजाब में 2500 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट सहित एक नया ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट होगा स्थापित : संजीव अरोड़ा

1500 से अधिक लोगों के लिए सीधे रोजगार के साथ साथ एमएसएमई के लिए व्यवसायिक के अप्रत्यक्ष अवसर होंगे पैदा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब को प्रमुख औद्योगिक हब बनाने और कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज जानकारी दी कि वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड (वीएसएसएल) जापान की आइची स्टील कॉरपोरेशन (एएससी) के संयुक्त उद्यम से लुधियाना जिले में एक नया ग्रीनफील्ड स्पेशल एवं अलॉय स्टील प्लांट स्थापित कर रहा है। यह परियोजना राज्य में टिकाऊ, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील निर्माण सुविधा स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रोजेक्ट संबंधी मीडिया से बातचीत करते हुए श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 2500 करोड़ रुपये है। अलॉय और स्पेशल स्टील की 5 लाख टन प्रति वर्ष (टीपीए) स्थापित क्षमता के साथ यह प्लांट घरेलू और वैश्विक ऑटोमोटिव आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह प्लांट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) तकनीक से ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन में कमी और शुद्ध स्टील उत्पादन सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि 500 करोड़ रुपये की लागत से एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र भागीदार कंपनी के सहयोग से प्लांट के संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि यह 500 करोड़ रुपये का निवेश 2000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट से अलग है।

उल्लेखनीय है कि यह परियोजना पंजाब में अधिकतम रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें 1500 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि पूरे राज्य में एम एस एम ई , सप्लायर्स और सेवा प्रदाताओं को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायिक अवसर प्राप्त होंगे। संजीव अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि यह परियोजना पंजाब के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर बनेगी और उन्नत व टिकाऊ स्टील उत्पादन में राज्य की अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेगी। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने के लिए उद्योगपतियों से सहयोग और मार्गदर्शन की अपील की।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.